existing fields and provision of new funds has been finalised by ONGC and submitted to Government for approval;

(b) if so, what are the broad details of the plan and whether the plan has since been approved by Government; and

(c) what targets have been fixed under the plan for being achieved during the Seventh Five Year Plan period?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI NAWAL KISHORE SHARMA): (a) to (c) ONGC proposes to test enhanced oil recovery processes in the fields and evaluate their performance to decide about their commercial applications. Nine EOR pilot projects have been approved for implementation during the seventh plan period at an estimated cost of about Rs. 60.7 crores. These are the polymer pilot in Sanand field, in *situ* combustion in *Balol* field in *situ* combustion in Lanwa, Steam flood in Balol, polymer flood in Jalora, micellar polymer in Ankleshwar, caustic flood in Sanand, LPG flood in Geleki Field and Co2 flood in Kalol field.

Viable industrial units

988. SHRI RAMCHANDRA BHARADWAJ: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have decided not to take over industrial units which have ceased to be viable; and

(b) if so, what steps are contemplated to ensure employment to workers of such industries and to recover the loans due from such units to nationalised banks and other public financial institutions?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) According to the policy guidelines issued by the Government in October, 1981, before taking a decision to take over an industrial undertaking, Government would satisfy itself that such undertaking can become viable in a reasonable period of time. The salient features of these guidelines have already been furnished in reply to Rajya Sabha Unstarred Question No. 700 on 15-7-82.

Banks and financial institutions are expected to formulate rehabilitation schemes in respect of units which, in their judgement, are potentially viable and nurse such units back to health so as eventually to recover their dues. In the case of non-viable units, the banks may recall the advances and take recourse to legal measures for recovering their dues. There is no specific scheme for ensuring alternative employment for workers displaced as a result of closure of industrial undertakings.

शिनौर के समुद्र तट पर विद्युत केन्द्र का स्थापित किया जाना

989. **श्री मीर्जा इर्शादबेग :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार द्वारा गुजरात नर्मदा ताप विद्युत केन्द्र (4×500 मेगावाट) योजना के अधीन बड़ौदा के समीप शिनौर के समुद्र तट पर 4×500 मेगावाट विद्युत केन्द्र की स्थापना किए जाने के संबंध में कोई अनुरोध किया गया है; और यह अनुरोध किस तारीख को भेजा गया था;

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) इसे कब तक पूरा कर दिय जाएगा ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) गुजरात बिजली बोर्ड ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को एक परियोजना

रिपोर्ट मई 1982 में प्रस्तुत की है जिसमें बड़ौदा जिले के शिनौर तालुक में नर्मदा ताप विद्युत परियोजना (4× 500 मेगावाट) स्थापित किए जाने की परिकल्पना है। रेल द्वारा कोयले की ढुलाई में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए गुजरात बिजली बोर्ड को कोयले की ढुलाई समुद्री मार्ग से करने, परियोजना को समुद्र तट के पास स्थापित करने तथा बहु ईंधन बायलरों के उपयोग पर विचार करने की सलाह दी गई है।

फॉसजीन और मिक (एम० आई० सी०) गसों पर आधारित उद्योग

990. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक किन-किन स्थानों पर फॉसजीन और मिक जहरीली गैसों पर आधारित उद्योग स्थापित हैं और उनकी संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन उद्योगी संयंत्रों में पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सुरक्षा प्रबंधों की निगरानी करने के लिए इनमें सुरक्षा कर्मियों का सूक्ष्म और कार्यकुशल दल तैनात किया गया है ?

रसायन और पैट्रोरसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) इस समय ऐसा कोई एकक प्रचालन में नहीं है जो अन्य उत्पादों के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में एम० आई० सी० का उपभोग कर रहा हो। देश में केवल अतुल प्राडक्ट्स लि०, बलसाद, गुजरात एक ऐसा एकक है जो फॉसजीन का उत्पादन कर रहा है। उन अनुसंधान प्रयोगशालाओं तथा औद्योगिक एककों के नाम तथा स्थान संलग्न विवरण में दिए गए हैं जिनको इस एकक ने फॉसजीन की आपूर्ति की।

(ख) और (ग) कारखाना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कारखानों में सुरक्षा व्यवस्थाओं पर निगरानी रखना राज्य सरकारों का कार्य है, जिन्हें सलाह दी गयी है कि खतरनाक प्रक्रियाओं पर आधारित संयंत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने में कोई कमी न रखें। इसमें ये शामिल होंगे—टास्क फोर्स/विशेषज्ञ दलों की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्यवाही करना, जिन्हें गठित करने के लिए उनसे अनुरोध किया गया है ताकि वे उन औद्योगिक एककों का सर्वेक्षण तथा शिनाख्त करें जो खतरनाक रसायनों का उत्पादन करते हैं या उन का व्यापार करते हैं, बहु-उद्देश्यीय निरीक्षण अभिकरण की स्थापना करना जो खतरों के सभी सुरक्षा पहलुओं का ध्यान रखेगा, पर्यावरणात्मक पहलू तथा ऐसे अभिकरण में बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करने सहित, निरीक्षण-सूची में शामिल करने के लिए संकट वाले क्षेत्रों की शिनाख्त करना ताकि ऐसे एकक के निरीक्षण को अर्थपूर्ण तथा प्रभावी बनाने के लिए नियमित निरीक्षण अभिकरणों की सहायता की जा सके, यह सुनिश्चित करना कि सभी खतरनाक रसायनों को चाहे वे प्रपुंज भण्डारण में हों या बन्द संयंत्रों में प्रक्रियाओं में, प्रबन्धकों द्वारा तत्काल निपटा दिया जाए।

सुरक्षा कार्मिकों की नियुक्ति का मामला सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में उठता है। सुरक्षा कार्मिक किन्हीं दंगों, फिसादों के मामले में सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की सुरक्षा के लिए होते हैं। परन्तु वे संयंत्र प्रचालनों या सुरक्षा व्यवस्थाओं पर निगरानी नहीं रखते।

विवरण

फॉसजीन पर आधारित उद्योगों की सूची

क्रमांक	उद्योग का नाम	स्थान
1.	सुकान कैमिकल्स	अहमदाबाद
2.	युनाइटेड कैमि०	बड़ौदा
3.	जे० कैम० इंडस्ट्रीज	अहमदाबाद
4.	आर्गेनो कैम० इंडस्ट्रीज	अहमदाबाद
5.	अलेम्बिक कैम० वर्क्स	बड़ौदा